जलवायु परविर्तन और खाद्य असुरक्षा

यह एडटिोरयिल 'द हदिू' में प्रकाशति "COP-27, in Egypt, Must Focus on Food Systems" लेख पर आधारति है। इसमें चर्चा की गई है कि खाद्य असुरक्षा कसि प्रकार जलवायु परविर्तन से संबंधति है और कमज़ोर समुदायों के लयि प्रत्यास्थता का नरि्माण कर जलवायु संकट और भुखमरी की समस्या से नपिटने के लयि क्या उपाय कयि जा सकते हैं।

संदर्भ

सरकारों, नागरकिों और नजिी क्षेत्र के बीच मज़बूत सहयोग और साझेदारी के साथ वर्ष 2030 तक वशि्व को भुखमरी से मुक्त करने और सतत् वकिास लक्ष्यों (SDGs) के लक्ष्यों की पूर्तकिरने के लयि वशि्व परविर्तन की कगार पर है ।

सर्वाधकि कमज़ोर लोगों की रक्षा के लयि UNFCCC के COP-26 शखिर सम्मेलन में योगदानकर्त्ता राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों द्वारा नए समर्थन के रूप में 356 मलियिन डॉलर की राशभिी जुटाई गई।

नश्चिति रूप से ये सभी प्रयास सराहनीय हैं, लेकनि वशि्व में खाद्य सुरक्षा का संकट अभी भी बना हुआ है और कोवडि-19 महामारी द्वारा इस समस्या को और गहरा ही कयिा गया है।

वैश्वकि खाद्य सुरक्षा सुनश्चिति करने के लयि वकिास एवं संवहनीयता के संतुलन, जलवायु परविर्तन के शमन, स्वस्थ, सुरक्षति एवं कफिायती भोजन की सुनश्चितिता और इसके लयि सरकारों एवं नजिी क्षेत्र की ओर से नविश की दशि में खाद्य प्रणाली की पुनर्कल्पना की जाने की आवश्यकता है।

जलवायु संकट और भुखमरी

- **जलवायु परविर्तन और खाद्य प्रणाली का अंतर्संबंध:** जलवायु संकट वैश्वकि खाद्य प्रणाली के सभी भागों को (उत्पादन से लेकर उपभोग तक) प्रभावति करता है।
    - यह भूमि एवं फसलों को नष्ट करता है, पशुधन का ह्रास करता है, मत्स्य पालन को कम करता है एवं बाज़ारों को आपस में जोड़ने वाले परविहन में कटौती करता है, जसिसे यह खाद्य उत्पादन, उपलब्धता, वविधिता, पहुँच और सुरक्षा को भी प्रभावति करता है।
        - इसके साथ ही, खाद्य प्रणालयिाँ भी पर्यावरण को प्रभावति करती हैं और जलवायु परविर्तन की वाहक हैं। आँकड़े बताते हैं कि खाद्य क्षेत्र वशि्व के लगभग 30% ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है।
    - COP-26 का आयोजन अग्रगामी संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शखिर सम्मेलन (UN Food Systems Summit) के बाद हुआ जो इस तथ्य के संदर्भ में 'वेक-अप कॉल' की तरह था कि खाद्य प्रणालयिाँ असमानता और बधायुक्त हैं क्योंकि 811 मलियिन लोग भूखे सोने को मज़बूर हैं।
- **जलवायु-भुखमरी संकट वर्तमान परदिृश्य:** वर्ष 2030 तक वैश्वकि भुखमरी और कुपोषण को उसके सभी रूपों में समाप्त करने का एजेंडा वकिट चुनौतयिों का सामना कर रहा है, क्योंकि जलवायु संकट लगातार बगिड़ता जा रहा है।
    - कोवडि-19 महामारी ने चरम भुखमरी की शकिार आबादी की संख्या को दोगुना (130 मलियिन से बढ़कर 270 मलियिन) करते हुए इस संकट को और गहन कर दयिा है।
    - **संयुक्त राष्ट्र वशि्व खाद्य कार्यक्रम** (WFP) के अनुसार, औसत वैश्वकि तापमान में पूर्व-औद्योगकि स्तर से 2 डगि्री सेल्सयिस की वृद्धि 189 मलियिन अतरिक्ति लोगों को भुखमरी की ओर धकेल देगी।
    - IPCC की नवीनतम रपिोर्ट में बताया गया है कि जलवायु संकट न केवल खाद्य उत्पादन और आजीवकिा को प्रभावति करेगा, बल्कि मल्टी-ब्रेडबास्केट वफिलताओं के माध्यम से पोषण को भी खतरा पहुँचाएगा।
- **कमज़ोर समूह-न्यूनतम उत्सर्जक, अधकितम पीड़ति:** कमज़ोर समुदाय, जनिका एक वशिाल बहुमत नरि्वाह कृष, मछली पकड़ने और पशुधन पालन पर नरि्भर है और जो जलवायु संकट में न्यूनतम योगदान करता है, अपने सीमति साधनों के साथ प्रभावों से सर्वाधकि हानि सहना जारी रखेंगे।
    - शीर्ष 10 सबसे अधकि खाद्य-असुरक्षति देश वैश्वकि कार्बन उत्सर्जन में 0.08% का योगदान करते हैं।
        - फसल वफिलता, जल की कमी और घटते पोषण स्तर से उन लाखों लोगों को खतरा है जो कृष, मछली पकड़ने और पशुधन पर नरि्भर हैं।
    - खाद्य सुरक्षा जाल जैसे सामाजकि सुरक्षा उपायों की अनुपस्थति खाद्य असुरक्षति लोगों को अस्तत्वि बनाए रखने के लयि मानवीय

सहायता पर निर्भर रहने हेतु मज़बूर करती है।

- **जलवायु संकट और खाद्य सुरक्षा के लिये WFP की पहल:** खाद्य उत्पादन, सुरक्षित आय और आघात सहने की क्षमता को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रति समुदायों को अनुकूल बनाने के लिये WFP उनके साथ कार्य कर रहा है। इसने 39 सरकारों का समर्थन किया है और यह उन्हें अपनी राष्ट्रीय जलवायु महत्त्वाकांक्षाओं को साकार करने में सहायता प्रदान कर रहा है।
    - वर्ष 2020 में WFP ने 28 देशों में जलवायु जोखिम प्रबंधन समाधान लागू किये, जिससे छह मिलियन से अधिक लोगों को लाभ हुआ ताकि वे जलवायु झटके और तनाव के प्रति बेहतर तरीके से तैयार हो सकें और तेज़ी से पुनरुद्धार कर सकें।
    - भारत में WFP और पर्यावरण मंत्रालय अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) से संभावित समर्थन के साथ अनुकूलन और शमन पर एक सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल विकसित करने की योजना बना रहे हैं।

आगे की राह

- **गरीबों के लिये लचीली व्यवस्था का निर्माण:** गरीब और कमज़ोर समुदायों के लिये अनुकूलन और लचीली व्यवस्था का निर्माण (Resilience-Building) खाद्य सुरक्षा के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
    - इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लोगों और प्रकृति पर जलवायु चरम घटनाओं के प्रतिकूल प्रभाव बढ़ते तापमान के साथ बढ़ते रहेंगे, सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान के अनुरूप और विकासशील देश पक्षकारों की प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं पर विचार करते हुए कार्रवाई एवं समर्थन (वित्त, क्षमता-निर्माण, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण) की वृहद्ता, अनुकूलन क्षमता की वृद्धि, प्रत्यास्थता के सुदृढ़ीकरण और भेद्यता को कम करने पर बल दिया जाना आवश्यक है।
- **भारत की भूमिका:** भारत को राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर जारी और अब पर्याप्त रूप से कार्यान्वित नीतिगत कार्य के साथ एक बड़ी भूमिका निभानी है।
    - उच्च कृषि आय और पोषण सुरक्षा के लिये इसे अपनी खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करते हुए इन्हें अधिक समावेशी और संवहनीय बनाना होगा।
    - जल के अधिक समान वितरण और संवहनीय एवं जलवायु आधारित कृषि के लिये बाजरा, दलहन, तिलहन, बागवानी की ओर फसल पैटर्न के विविधीकरण की आवश्यकता है।
- **अनुकूलन वित्त:** विकासशील देशों में अनुकूलन का समर्थन करने के लिये जलवायु वित्त (climate finance) को बढ़ाने पर विकसित देशों द्वारा हाल में जताई गई प्रतिबद्धता एक स्वागत योग्य संकेत है।
    - हालाँकि अनुकूलन के लिये मौजूदा जलवायु वित्त का स्तर और हितधारकों का आधार बदतर होते जलवायु परिवर्तन प्रभावों का मुकाबला कर सकने के लिये अपर्याप्त है।
    - बहुपक्षीय विकास बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान और निजी क्षेत्र को जलवायु योजनाओं को साकार करने हेतु (विशेष रूप से अनुकूलन के लिये) आवश्यक वृहत संसाधनों की आपूर्ति के लिये वित्त जुटाने में और तेज़ी लानी होगी।
    - विभिन्न पक्षकारों को अनुकूलन के लिये निजी स्रोतों से वित्त जुटाने हेतु नवीन दृष्टिकोणों और साधनों का पता लगाना जारी रखना होगा।
- **जलवायु-भुखमरी संकट से निपटने के लिये बहु-आयामी दृष्टिकोण:**
    - कमज़ोर समुदायों की आजीविका की रक्षा और उनमें सुधार के माध्यम से प्रत्यास्थी आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा समाधान का सृजन करना।
    - पोषण सुरक्षा के लिये बाजरा जैसे जलवायु-प्रत्यास्थी खाद्य फसलों का अनुकूलन।
    - उत्पादन प्रक्रियाओं एवं संपत्तियों पर महिलाओं के नियंत्रण एवं स्वामित्व को सक्षम बनाना और मूल्यवर्द्धन एवं स्थानीय समाधानों में वृद्धि करना।
    - जलवायु सूचनाओं एवं तैयारियों के साथ छोटे किसानों के लिये संवहनीय अवसरों, वित्त तक पहुँच और नवाचार के सृजन के माध्यम से प्रत्यास्थी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना।
    - भेद्यता विश्लेषण के लिये नागरिक समाज एवं सरकारों की क्षमता एवं ज्ञान का निर्माण करना ताकि खाद्य सुरक्षा और जलवायु जोखिम के बीच की संबंध को संबोधित करते हुए खाद्य सुरक्षा की वृद्धि की जा सके।
- **संवहनीय खाद्य प्रणाली:** उत्पादन, मूल्य शृंखला और उपभोग में संवहनीयता हासिल करनी होगी। जलवायु-प्रत्यास्थी फसल पैटर्न को बढ़ावा देना होगा। संवहनीय कृषि के लिये किसानों को इनपुट सब्सिडी प्रदान करने के बजाय नकद हस्तांतरण किया जा सकता है।
- **गैर-कृषि क्षेत्र की भूमिका:** श्रम-प्रधान विनिर्माण और सेवाएँ कृषि पर से दबाव को कम कर सकती हैं।
    - छोटे जोतदारों और अनौपचारिक श्रमिकों के लिये कृषि से होने वाली आय पर्याप्त नहीं है।
    - ग्रामीण MSMEs और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सशक्त बनाना इस समाधान का एक अंग होगा।

निष्कर्ष

खाद्य प्रणालियों की पुनर्कल्पना के लिये इसे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन के नज़रिये से देखना होगा, जहाँ उन्हें हरित और संवहनीय बनाने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन एवं महामारियों के प्रति लचीला बनाना भी आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न: वैश्विक स्तर पर जलवायु संकट और बढ़ती खाद्य असुरक्षा के बीच के अंतर्संबंध की व्याख्या कीजिये और इन समस्याओं से एक साथ निपटने के उपायों के सुझाव दीजिये।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/climate-change-and-food-insecurity